INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 11, Issue: 4 | October – December 2024

एक समय में ग्रामीण क्षेत्र के पास के पारंपरिक अर्थव्यवस्था (बाजार) की छलांग का अर्ध-सामंती ताकतों के बीच टकराव

***Prabhat Kumar Singh**
*Research Scholar, Department of History, Purnea University, Purnia, Bihar (India).
* Email: prabhatsingh.1470@gmail.com

इस का उद्देश्य पारंपरिक भारतीय अर्थव्यवस्था पर विपणन और मुद्रीकरण द्वारा लाए गए प्रभावों और संशोधनों की रूपरेखा तैयार करना है। 1970, 1980 और 2000 में लेखकों ने बिहार के पूर्णिया जिले के दो गाँवों में अपना शोध किया। तुलनात्मक शोध के अनुसार, मजदूरी पुनर्भुगतान के पारंपरिक तरीके, जैसे कि बटाईदार खेती, तब भी बनी रही जब अर्ध-सामंती तंत्र में गिरावट आई और कृषि राजस्व के साथ श्रम लागत में वृद्धि हुई। उच्च मृत्यु दर, महिला रोग और अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं पिछले दशक की बुराइयों में से थीं जो अस्तित्व में रहीं, न केवल सामाजिक संरचनाओं की कमियों को उजागर करती थीं, बल्कि बहुत आवश्यक आधिकारिक समर्थन की कमी भी थी।एन अप्रैल 1999 में, हम पूर्वोत्तर बिहार में पूर्णिया जिले के कस्बा ब्लॉक के दो आस-पास के गांवों में थोड़े समय के लिए लौटे, जहाँ हमने 1971 और 1981 में रोजगार और गरीबी सर्वेक्षण किया था। 1971 के शोध ने जांच की कि बड़े पैमाने पर सार्वजनिक कार्य परियोजनाओं के पास कई समुदायों में सार्वजनिक कार्य परियोजनाओं ने ग्रामीण गरीबी को कैसे प्रभावित किया। [जी. रॉजर्स, 1973]। गरीब लोगों की जीवन स्थितियों में दीर्घकालिक परिवर्तनों की जांच करने के लिए, हम 1981 में इन समुदायों के बहुमत में लौट आए [जी रॉजर्स और आर रॉजर्स 1984]। हमने कई घरों के साथ साक्षात्कार किए, जिनमें से ज्यादातर कृषि रोजगार में लगे हुए थे, और दोनों अवसरों पर सामान्य गाँव की जानकारी एकत्र की। इनमें से कई परिवारों से 1971 की तरह 1981 में फिर से पूछताछ की गई थी।

परिचय:

हमने 1999 में इनमें से दो गाँवों पोखरिया और दुबैली विश्वासपुर का फिर से दौरा किया। हमने एक ही परिवार के कई लोगों से बात की, जो आम तौर पर दूसरी पीढ़ी के निवासी थे, और हमने घटनाओं और परिवर्तनों, रोजगार और आय के रुझानों, आर्थिक वातावरण और बुनियादी ढांचे, सामाजिक संस्थानों और उनके और अन्य ग्रामीणों के साथ श्रम बाजार पर चर्चा की। इस बार-बार की गई यात्रा की छोटी अवधि के कारण एक कठोर, वैज्ञानिक सर्वेक्षण संभव नहीं था। हालांकि, पिछली यात्राओं ने लोगों के साथ एक मजबूत संबंध बनाना और परिवर्तन की मुख्य विशेषताओं को जल्दी से पहचानना आसान बना दिया। सैकड़ों अन्य बस्तियों की तरह, ये दोनों उत्तरी गंगा के मैदान के केंद्र में स्थित हैं, जहाँ भूजल की प्रचुरता है और अक्सर सतह के पानी की अधिकता है। उन्हें पहली बार (1970 में) नहर निर्माण के लिए उनकी निकटता के कारण चुना गया था, जो अब पूरा हो गया है और जैसा कि यह निकला, स्थानीय बस्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इन दिनों, सात किलोमीटर की सड़क जो आंशिक रूप से सतह पर है, लेकिन मानसून के दौरान खराब हो जाती है और कभी-कभी कट जाती है, उन्हें बाहरी दुनिया, ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ती है। जैसा कि पूर्णिया गाँवों में जाता है, एक बहुत छोटा है, 1992 में केवल 660 निवासियों के साथ; दूसरा लगभग 3,600 निवासियों के साथ पर्याप्त है। मूल रूप से, दोनों कृषि हैं। एक समूह में अधिकांश छोटे किसान हैं, जबकि दूसरे समूह में बड़े जमींदार और खेतिहर मजदूर हैं। एक में बहुसंख्यक मुसलमान और कुछ अनुसूचित जातियाँ हैं, जबकि दूसरी पूरी तरह से हिंदू है और ज्यादातर "पिछड़ी" जातियों से बनी है। इस क्षेत्र में कई अन्य प्रकार के गाँव हैं, जिनमें बेहतर या बदतर कृषि-सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, बेहतर या खराब संचार और विभिन्न सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, इस प्रकार यह दावा नहीं किया जाता है कि ये गाँव प्रतिनिधि हैं। हालाँकि, वहाँ जो हो रहा है वह शायद इस क्षेत्र में कहीं और भी दोहराया जा रहा है, हालांकि कुछ हद तक। 1970 और 1981 के बीच की परिस्थितियाँ 1970 के दशक में ये बस्तियाँ बेहद गरीब थीं। कृषि राजस्व और उत्पादन दोनों ही खराब थे। दो मुख्य फसलें धान और जूट थीं। चूंकि जूट, एक वाणिज्यिक फसल, ग्रामीण

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 11, Issue: 4 | October – December 2024

अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इस क्षेत्र को लंबे समय से इस क्षेत्र के वाणिज्यिक नेटवर्क में शामिल किया गया है। हालाँकि, दुनिया भर के बाजार के अस्थिर और आम तौर पर कम मूल्य निर्धारण के कारण यह कृषि विस्तार का स्रोत साबित नहीं हुआ है। शेष कृषि क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा गेहूं और दालों से बना था।
चूंकि कोसी नहर प्रणाली का निर्माण किया जा रहा था और हरित क्रांति ने सिंचित भूमि पर कृषि उत्पादन को तेजी से बढ़ाने के अवसर प्रस्तुत किए, इसलिए पुरिया ने 1970 के दशक की शुरुआत में कुछ आशावाद का अनुभव किया। हालाँकि, इन बस्तियों में नहर प्रणाली सिंचाई की आपूर्ति नहीं करती थी और उन्हें बाढ़ और जलभराव के लिए अधिक संवेदनशील बनाती थी। कृषि सुधारों को अपनाने के लिए बस्तियाँ सुस्त थीं, और खराब जल प्रबंधन ने उनके विस्तार में बाधा उत्पन्न की। 1970 के दशक के मध्य में उच्च उपज देने वाली गेहूं की किस्मों, रासायनिक उर्वरकों और कुछ ट्यूबवेल सिंचाई की शुरुआत के कारण किसानों का केवल एक छोटा प्रतिशत गेहूं के लिए लगाए गए क्षेत्र में वृद्धि के बारे में चिंतित था। 1981 में, किसानों का केवल एक छोटा प्रतिशत उच्च उपज देने वाली धान की किस्मों का उपयोग कर रहा था जो 1970 के दशक के अंत में शुरू की गईथी।

जलमग्न खेत उच्च उपज देने वाली किस्मों का समर्थन नहीं करेंगे। 1970 के दशक में लगभग हर सक्रिय पुरुष कृषि में कार्यरत था, जो खेत मजदूरों और किसानों के बीच लगभग समान रूप से विभाजित था। कम से कम दो-तिहाई, यदि अधिक नहीं, तो जमींदार समुदाय के छोटे या सीमांत किसान थे, 40% परिवारों के पास कोई भूमि नहीं थी, और जोत मामूली थी। लगभग 15% भूमि को बटाईदार माना जाता था, और छोटे उत्पादकों के बीच किरायेदारी आम थी। अधिकांश मजदूरों के पास रुक-रुक कर रोजमर्रा का काम था। 1981 में, पारिश्रमिक का नकद घटक महिलाओं के लिए 1.25 रुपये और बच्चों के लिए 1.25 रुपये था। दोनों गांवों में वयस्क पुरुष आकस्मिक मजदूरों को प्रति दिन 1.50 रुपये मिलते थे, जिसमें नाश्ता और दोपहर का भोजन शामिल था। कटाई के अपवाद के साथ, जिसे फसल के एक हिस्से के साथ मुआवजा दिया गया था, वेतन स्थिर था। यदि वर्तमान मूल्य निर्धारण पर अनाज में परिवर्तित किया जाता है, तो वयस्क पुरुषों (भोजन सहित) के लिए इस वेतन का कुल मूल्य 1,350 से 1,550 ग्राम अनाज या प्रति दिन लगभग 5,000 कैलोरी होगा। यह अविश्वसनीय रूप से कम है क्योंकि (i) अनाज के अलावा अन्य आवश्यकताएं हैं, भले ही यह खपत का प्राथमिक स्रोत हो; (ii) श्रमिक और उनके आश्रितों को भुगतान किया जाना था; और (iii) वेतन वार्षिक रूप से केवल 200 से 250 दिनों के काम के लिए उपलब्ध था। वेतन में भी वृद्धि नहीं हो रही थी। यदि कुछ भी हो, तो 1981 में 1971 की तुलना में और भी कम आय देखी गई।

1981 में पोखरिया का वास्तविक मजदूरी सूचकांक 76 था, जबकि कृषि श्रमिकों के मूल्य सूचकांक (1971 = 100) के आधार पर दुबैली विश्वासपुर का 82 था। केवल अनाज की कीमतों पर विचार करने पर भी वास्तविक आय अनिवार्य रूप से स्थिर थी, जो समग्र रूप से सूचकांक की तुलना में कम हो गई थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इन कमाई को देखते हुए कृषि मजदूरों की मृत्यु दर अधिक थी। शिशु मृत्यु दर प्रति हजार 300 से अधिक थी, और 1971-1981 तक कृषि मजदूरों के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 30 से कम होने का अनुमान था। [जे. और जी. रॉजर्स, 1984] इस वजह से, जनसंख्या वृद्धि तुलनात्मक रूप से कम थी, दशक के दौरान पोखरिया में केवल 6% की वृद्धि देखी गई और दुबैली विश्वासपुर में 20% से थोड़ी कम वृद्धि (जनगणना के आंकड़ों के आधार पर) देखी गई, जबकि ग्रामीण कस्बा और ग्रामीण बिहार में क्रमशः 35% और 24% की वृद्धि देखी गई। 'हलवाहा', या संलग्न हल चलाने वाले, जिन्हें वार्षिक आधार पर भुगतान किया जाता था, अन्य आकस्मिक कृषि मजदूरों के अलावा एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक थे। कई 'चारवाहा' (10 से 16 वर्ष की आयु के बच्चे और किशोर जो विभिन्न नौकरियों में लगातार काम करते हैं, ज्यादातर घरेलू, कृषि और पशुधन संचालन से संबंधित) और घरेलू कर्मचारी भी उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त, अधिकांश कृषि कंपनियों ने आकस्मिक आधार पर बच्चों को काम पर रखा। महिलाओं की अत्यधिक कम भागीदारी दर, जो मुख्य रूप से कटाई तक सीमित थी और मुख्य रूप से निम्न जाति के घरों में देखी गई थी, आर्थिक गतिविधियों में बच्चों की उच्च भागीदारी के विपरीत थी। 1971 और 1981 के बीच कृषि उत्पादन में

महिलाओं की भागीदारी में कुछ सुधार हुआ होगा, लेकिन यह अभी भी काफी कम थी। केवल कुछ ही प्रतिशत परिवारों के पास आय के प्रमुख स्रोत के रूप में गैर-कृषि व्यवसाय थे, और इनमें ज्यादातर वाणिज्य और सेवाएं शामिल थीं। हालाँकि, गरीब परिवारों के पास सहायक कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला थी, जिनमें से कई मौसमी थे, जैसे कि घर बनाना, खुदाई करना, मछली पकड़ना, शादियों में प्रदर्शन करना, पान बेचना, गाय को काटना और टोकरी बनाना। महिलाओं को दाई, टोकरी, खाद्य प्रसंस्करण (जिसे "चूड़ा बनाने" के रूप में भी जाना जाता है) और घरेलू कार्यों में नियुक्त किया जाता था। कुछ किसानों ने अन्य शहरों में हर दिन वेतन के लिए काम करना शुरू कर दिया था, हालांकि दूरी और अपर्याप्त संपर्क के कारण यात्रा करना मुश्किल था। कुछ लोगों के धीमी खेती के मौसम के दौरान भूमि पर काम करने के लिए बस्ती से बाहर जाने की खबरें थीं, ज्यादातर असम में। सरकारी सेवा और निजी कंपनियों (पश्चिम एशिया में दो) में बस्ती के बाहर कुछ स्थायी रोजगार कुछ शिक्षा वाले व्यक्तियों के बीच देखा गया था। सुविधाएं अपर्याप्त थीं। अमीर लोग फूस की छतों और मिट्टी की दीवारों वाले घरों में रहते थे। गरीब लोग पुआल और बांस से बनी झोपड़ियों में रहते थे। हालाँकि 1970 के दशक में सड़क संचार में काफी सुधार देखा गया, फिर भी वे सार्वजनिक परिवहन के लिए अपर्याप्त थे। 1981 में दोनों गाँवों में बिजली नहीं थी।

दूबैली विश्वासपुर में एक मदरसा था, लेकिन निकटतम सरकारी प्राथमिक विद्यालय 1.5 किमी दूर था। 1981 में, लगभग 20% पुरुषों और 5% महिलाओं को साक्षर होने की सूचना दी गई थी, और स्कूली उम्र की आबादी का केवल 30% स्कूल में नामांकित होने की उम्मीद थी, जिसमें प्रत्येक महिला के लिए दो लड़के थे। यद्यपि साक्षरता दर बढ़ रही थी, फिर भी वे बहुत कम थी। अधिकांश स्वास्थ्य सेवाएं अप्रशिक्षित नीम हकीमों द्वारा प्रदान की गई थीं। कस्बा निकटतम सरकारी मुख्य स्वास्थ्य सुविधा, निजी चिकित्सकों और औषधालयों का घर था। उन दिनों जब गाँव का बाजार संचालित किया जाता था, क्वाक्स एक सर्जरी चलाते थे जहाँ लोग दवाएँ खरीद सकते थे। अनुचित जल प्रबंधन के कारण कृषि की प्रगति बाधित हुई। स्थिति को सुधारने के लिए, फील्ड नहरों, जल निकासी, ट्यूबवेल और भूमि समतल करने पर महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता थी। भले ही उत्कृष्ट पैदावार के कई उदाहरण, विशेष रूप से गेहूं में, बताते हैं कि भूमि में अच्छी क्षमता थी, लेकिन नवाचार या निवेश करने में अनिच्छा थी। भूमि पर जनसंख्या के दबाव के कारण 1981 में औसत पैदावार बढ़ाने और वैकल्पिक राजस्व स्रोतों की तलाश करने की आवश्यकता पड़ी। हालांकि, व्यावसायिक संरचना में विविधता का अभाव था और औपचारिक स्कूली शिक्षा पीछे रह गई। केवल कुछ ही धनी परिवारों के पास गाँव के बाहर उन्हें उपलब्ध कराई गई शैक्षिक संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक संसाधन और परिस्थितियाँ थीं। हालांकि, एक अनैच्छिक, स्थिर ग्रामीण वातावरण ने भूमिहीनों, अकुशल और अनपढ़ लोगों के लिए आर्थिक गतिशीलता के लिए बहुत कम या कोई अवसर प्रदान नहीं किया। प्रधान एच. एस. प्रसाद (1987) और अन्य लोगों द्वारा निर्मित अर्ध-सामंती मॉडल दुबैली विश्वासपुर की परिस्थितियों का पर्याप्त वर्णन करता प्रतीत होताहै।[2].

असमान भूमि वितरण, किरायेदारी, अस्थायी और संलग्न कार्य का संयोजन और ऋण सामाजिक और आर्थिक संरचना की नींव थे। गाँव के जमींदार अभिजात वर्ग पर श्रमिक वर्गों की निर्भरता इन सभी प्रक्रियाओं द्वारा सुनिश्चित की गई थी, जिसने अवसरों और आय के अत्यधिक असमान वितरण को जारी रखने की अनुमति दी। छोटे उत्पादकों के पास निवेश करने के लिए धन की कमी थी, और अभिजात वर्ग ने सुधार और विकास में बहुत कम रुचि दिखाई, जिससे इस वितरण व्यवस्था को आधार बनाने वाली निर्भरता और अधिकार को खतरा हो सकता है। नतीजतन, भले ही कृषि निवेश में महत्वपूर्ण संभावित रिटर्न था, "नवाचार की गति धीमी थी"। छोटी बस्ती पोखरिया में दुबैली के जमींदारों की परत नहीं थी। हालाँकि, किरायेदारी और संलग्न श्रम उतने ही प्रचलित दिखाई दिए, जितना कि वे थे, क्योंकि कुछ किसानों के साथ एक छोटे से समुदाय के रूप में, यह बड़े पड़ोसी गांवों पर निर्भर था, जहाँ समान रीति-रिवाज प्रबल थे। नतीजतन, आर्थिक ठहराव के सामान्य मुद्दे ने दोनों बस्तियों को प्रभावित किया। 2001 में दूसरा संशोधन अप्रैल 2005 में परिवर्तन के संकेत मिले। दुबैली विश्वासपुर में सड़क के किनारे, एक चाय की दुकान, एक छोटी फार्मेसी, एक बाइक मरम्मत की दुकान और कुछ अन्य दुकानों सहित प्रतिष्ठानों का एक संग्रह

उभरा था। एक ऐसी अर्थव्यवस्था में जिसका पहले शायद ही मुद्रीकरण किया गया था, यह एक नया संकेत था कि खर्च करने के लिए पैसा था। गाँव की सड़क अभी भी खराब स्थिति में थी, जिन पुलों को पिछले साल की बाढ़ के कारण ठीक करने की आवश्यकता थी और जिन हिस्सों से मुश्किल से गुजरना पड़ता था।

लेकिन इसका उपयोग साइकिल रिक्शा द्वारा किया जा रहा था। हालाँकि गाँवों में दूरसंचार और बिजली लाई गई थी, लेकिन ग्रामीण बिहार में समस्या यह थी कि भौतिक संपर्क स्थापित होने के बावजूद बिजली उपलब्ध नहीं थी। यह बताया गया था कि जनवरी 2000 में शुरुआती हुकअप के बाद पोखरिया को केवल दस दिनों के लिए बिजली मिली थी। दुबैली विश्वासपुर का केवल एक क्षेत्र था जिसमें बिजली का कनेक्शन था। फिर भी, तारों का दृश्य चौंका देने वाला था, एक या दो टेलीविजन एरियल (दोनों समुदायों के पास टेलीविजन थे, हालांकि वे अस्थिर बिजली के कारण बैटरी पर चलते थे) और एक संचार हवाई की उपस्थिति का उल्लेख नहीं करना था। इमारतें एक और स्पष्ट परिवर्तन का विषय थीं। कुछ (ज्यादातर अधूरे) ईंट के घर कम आय वाले परिवारों के लिए सरकार द्वारा वित्त पोषित निर्माण कार्यक्रम का परिणाम थे, और अधिक पक्के आवास अक्सर दिखाई देते थे। पोखरिया में एक प्राथमिक विद्यालय का निर्माण किया जा रहा था, जबकि दूबैली में एक विद्यालय पहले ही स्थापित किया जा चुका था। जल आपूर्ति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति। चाहे सरकार द्वारा स्थापित किया गया हो या निजी तौर पर, ऐसा प्रतीत होता था कि हर परिवार के पास अब पास के हैंडटिम्प तक पहुंच थी। कई लोगों के पास एक पंप था जिसकी कीमत 1,300 रुपये थी। कृषि का विकास स्पष्ट रूप से, कृषि ने कुछ प्रगति की है। हालांकि नहर सिंचाई अभी भी अनुपस्थित थी, 1981 के बाद से पंपसेट और ट्यूबवेल की संख्या तीन गुना हो गई है। इससे 50% भूमि की सिंचाई संभव हो गई। इसका प्राथमिक ध्यान गेहूं पर था, जिसकी खेती वर्तमान में खेती योग्य भूमि के लगभग आधे हिस्से में दूसरी फसल के रूप में की जाती है, जो 1981 में 10 से 15 प्रतिशत थी। हालांकि, हमारी यात्रा के समय लगभग 5% खेत में सिंचित गरमा (ग्रीष्मकालीन) धान भी उगाया जा रहा था। चूँकि पहले गर्मियों में लगभग बहुत कम खेती की जाती थी, इसलिए यह एक तीव्र प्रस्थान था। हालाँकि, यह कुछ हद तक भ्रामक साबित हुआ क्योंकि धान को विफल गेहूं की फसल के बदले में लगाया गया था, और गर्मियों की खेती के महंगे खर्च के बारे में कई शिकायतें थीं।3. फिर भी, ट्यूबवेल ने एक फॉलबैक विकल्प प्रदान किया जहां पहले कोई नहीं था। 1981 की तुलना में, जब यह 130 और 150 के बीच था, 2000 में समग्र फसल तीव्रता 165 और 185 के बीच होने का अनुमान लगाया गया था। फसल के पैटर्न में प्राथमिक अन्य बदलाव रबी और जूट की दालों में कमी थी, जो आंशिक रूप से गेहूं में वृद्धि के कारण हुआ था। उस मिट्टी पर बहुत कम उत्पादन किया जा सकता है जहाँ अभी भी जूट की खेती की जाती है, जो बाढ़ के प्रति इसके लचीलेपन का संकेत है। नई फसलें कम थीं। बिहार में, सूरजमुखी और अन्य तिलहनों के लिए लगाए गए क्षेत्र में वृद्धि हुई है, लेकिन इन गांवों में केवल एक या दो प्रदर्शन भूखंड थे, और कई लोग नई फसलों को पेश करने पर विचार करने के लिए अनिच्छुक थे क्योंकि उन्हें बहुत खतरनाक माना जाता था। वहाँ थोड़ा मक्का उगाया जा रहा था। भदाई से धान गायब हो गया था। 1981 की तरह, किसानों की प्राथमिक चिंता बाढ़ के महत्वपूर्ण जोखिम और उर्वरक और सिंचाई की उच्च कीमतें थीं, जो निवेश पर कम अनुमानित रिटर्न देती हैं। औसतन पैदावार बढ़ गई है। 1999 में "सामान्य" गेहूं की पैदावार अक्सर लगभग 2,000 किलोग्राम/हेक्टेयर बताई गई थी। हालांकि यह 1981 में दर्ज की गई 600-2,600 किलोग्राम की सीमा के भीतर है, कुछ किसान उस समय उच्चतम उपज प्राप्त करने में सक्षम थे, और सिंचाई के विकास और उर्वरक उपयोग में सहवर्ती वृद्धि के कारण औसत उपज निस्संदेह महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी है। उर्वरक अनुप्रयोग के आधार पर धान की पैदावार 1981 में 1,300-2,400 किग्रा/हेक्टेयर से बढ़कर 2000 में 2,000-3,000 किग्रा/हेक्टेयर हो गई। ये उपज विशिष्ट हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 2000 की गेहूं की फसल पर कीटों का हमला हुआ था और इसकी पैदावार बेहद कम थी, जबकि धान की अधिकांश फसल 1998 में बाढ़ से नष्ट हो गई थी। यह स्पष्ट है कि खेती के तहत भूमि की मात्रा बहुत अधिक उत्पादक हो गई है। परिमाण के एक क्रम की गणना की जा सकती है, लेकिन सटीक अनुमान प्रदान करने के लिए फसलों और पैदावार के अधिक गहन लेखांकन की आवश्यकता होगी। साल दर साल भारी उतार-चढ़ाव उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्तर।

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 11, Issue: 4 | October – December 2024

गेहूं और धान की पैदावार में वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्पादन में 25-30% की वृद्धि हुई है, और फसल की तीव्रता में वृद्धि ने अतिरिक्त 20% वृद्धि में योगदान दिया है। 18 वर्षों के दौरान, कुल प्रतिशत 40 से 45 प्रतिशत के बीच हो सकता है।4. स्वाभाविक रूप से, हालांकि, इसकी तुलना उस समय की जनसंख्या वृद्धि से की जानी चाहिए। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, उत्पादन वृद्धि का अधिकांश हिस्सा 1981 और 1991 के बीच 33% (डुबैली) और 40% (पोखरिया) की जनसंख्या वृद्धि द्वारा अवशोषित किया जाएगा। 1991 और 1999 के बीच आठ वर्षों में जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए, यह संभावना है कि भूमि उत्पादकता में वृद्धि के बावजूद प्रति निवासी कृषि उत्पादन मात्रा के संदर्भ में नहीं बढ़ा है। उत्पादकों के वास्तविक राजस्व पर प्रभाव खेती की लागत से भी प्रभावित होता है, जो श्रमशक्ति के खर्च में तेज वृद्धि के साथ-साथ उर्वरक और सिंचाई की कीमत के कारण काफी बढ़ गई है। इसके विपरीत, 1981 से, कृषि के पक्ष में व्यापार की शर्तों के लिए एक निरंतर प्रवृत्ति रही है; 1996-1997 में, व्यापार सूचकांक की शर्तें, जो 1981-1982 में 88.7 थी, 106.1 तक पहुंच गई। हालाँकि, ऐसा नहीं लगता है कि व्यापार के संदर्भ में यह परिवर्तन बढ़ती मजदूरी और अन्य इनपुट कीमतों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त होगा। इसलिए, यह अत्यधिक संभावना है कि प्रति व्यक्ति वास्तविक कृषि आय में कमी आई है, या अधिक से अधिक, अपरिवर्तित रही है।5. यह गाँव के जमींदारों के साथ बातचीत के अनुरूप है, जिन्होंने महसूस किया कि 1980 के दशक की शुरुआत की तुलना में उनकी परिस्थितियाँ बदतर हो गई थीं। श्रम बाजार पर मजदूरी यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि कृषि का इतना मिश्रित रिकॉर्ड था। मजदूरी दरें सबसे बड़ा आश्चर्य था। वास्तव में, वे 1970 के दशक में स्थिर या घटते जा रहे थे, लेकिन अब उनका मूल्य आसमान छू गया है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, 1981 में औसत आकस्मिक दैनिक आय 1.50 रुपये थी, जिसमें नाश्ता और दोपहर का भोजन शामिल था और 1,350-1,550 ग्राम अनाज के बराबर था। 1999 में वेतन बढ़कर नकद में लगभग 30 रुपये हो गया, जो 20 रुपये + 1 किलोग्राम अनाज के बराबर है। अनाज में भुगतान के पक्ष में, एक प्रकार के वेतन के रूप में दोपहर का भोजन गायब हो गया था (कुछ खातों ने संकेत दिया कि लोगों को दोपहर में काम पर रखने की कोशिश करने के लिए अब समय-समय पर भोजन की पेशकश की जाती थी) इन वेतनों में कुछ अंतर था; कहा जाता था कि ये 25 रुपये से लेकर 35 रुपये तक थे। चराई के लिए वेतन 30 रुपये से 40 रुपये के बीच था। पोखरिया के चामरू महलदार के अनुसार, पुरुषों को केवल 15 रुपये (अतिरिक्त भुगतान) मिल सकते हैं, जबकि मेहनती श्रमिकों को अधिक मिलता है। हालांकि अभी भी महिला मजदूरी की कमी थी, महिलाओं को कम भुगतान किया जाता था-20 रुपये नकद या 8-15 रुपये और आधा किलोग्राम चावल और आधा किलोग्राम आटा निराई या प्रत्यारोपण के लिए। यह दो मायनों में बदलाव है। सबसे पहले, सीजन और यहां तक कि कर्मचारी दोनों के हिसाब से कमाई में बहुत अधिक अंतर था। सबसे बढ़कर, हालांकि, वास्तविक रूप से वेतन स्तर में काफी वृद्धि हुई है। जब हमने दौरा किया, तो बस्ती में चावल की कीमत लगभग 10.50 रुपये थी, और गेहूं के आटे की कीमत लगभग 7.50.7 रुपये थी। दैनिक वेतन के बराबर अनाज चावल के लिए लगभग तीन किलोग्राम और गेहूं के लिए चार किलोग्राम था। इस प्रकार, 1981 से, खाद्यान्न का वास्तविक मूल्य कम से कम दोगुना हो गया है। इसके अलावा, मजदूरी का एक बहुत अधिक प्रतिशत नकद में भुगतान किया गया था, जो दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था अधिक मौद्रिक रूप से उन्मुख हो गई थी। इसी तरह के निष्कर्ष तब प्राप्त होते हैं जब गणना में कृषि श्रम के लिए मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है। 1981 में, मजदूरी का मौद्रिक मूल्य 3.40 रुपये से 3.90 रुपये तक था। 1980 = 150 के आधार पर, अप्रैल 1999 में बिहार में कृषि श्रम के लिए मूल्य सूचकांक 387.8 होने का अनुमान है। अप्रैल 1999 में मजदूरी 6.46 रुपये से 9.04 रुपये के बीच थी, जो 1981 की कीमतों के अनुरूप है। यह इंगित करता है कि मजदूरी वास्तविक रूप से दोगुनी हो गई है, सीमा के निचले हिस्से में 90% वृद्धि और सीमा के शीर्ष में 130% की वृद्धि दिखाई दे रही है।

यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि फसल का हिस्सा, मजदूरी आय का दूसरा प्रमुख घटक, वास्तविक मजदूरी में इस भारी वृद्धि को नहीं दर्शाता है। सामान्य परिस्थितियों में, फसल का हिस्सा-आम तौर पर मजदूरों के लिए फसल का सातवां हिस्सा-1970 और 1980 के दशक की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण आय पूरक प्रदान करता था, जिससे दैनिक भुगतान का उत्पादन होता था जो नियमित मजदूरी के काम की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक था। वर्तमान स्थिति को अद्यतन किया गया है। यह

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 11, Issue: 4 | October – December 2024

आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण है कि वेतन अब उत्पादन का केवल नौवां हिस्सा है। यह बदलाव 1981 में ही शुरू हुआ था, जब अन्य सभी फसलों के लिए सातवें हिस्से की तुलना में सिंचित गेहूं को नौवां हिस्सा मिला था। अब सभी फसलों को नौवें हिस्से का एक हिस्सा मिलता है।

बढ़ती पैदावार के कारण हर दिन निवेश की जाने वाली राशि में वृद्धि होने की संभावना है, लेकिन शेयर की गिरावट से यह असंतुलित हो गया है, और वास्तविक वेतन में बहुत कम बदलाव आया है। 1999 की धान की फसल में, फसल के उत्पादन और श्रम की तीव्रता के आधार पर समतुल्य दैनिक वेतन 3.0 किलोग्राम से 8 किलोग्राम अनाज के बीच बताया गया था। ठीक यही धान की कटाई की सीमा है जिसे 1971 में प्रलेखित किया गया था। दोनों वर्षों में, एक औसत आंकड़ा लगभग 4 किलो प्रतीत होता है। यह धान की फसल के दौरान लगभग 3.0 किलोग्राम चावल के बराबर होगा, जिसकी कीमत 1999 में लगभग 25 रुपये या औसत दिन की आय से कम होगी। जूट की कटाई में एक दिन के काम से एक से दो किलोग्राम जूट का उत्पादन होता था, जिसे पांच-छह रुपये प्रति किलोग्राम में बेचा जा सकता था।10. चार किलोग्राम गेहूं की कीमत लगभग तीस रुपये होगी, जो लगभग औसत दैनिक आकस्मिक मजदूरी के बराबर है।10. यह कुल आय नियमित मजदूरी से अर्जित होने वाली आय की तुलना में काफी कम है और 1981 की तुलना में काफी कम है। कृषि-संस्कृति में प्रवासन प्रवृत्तियों की भूमिका वेतन पैटर्न में तेज बदलाव के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती है। एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन छोटे किसानों और कृषि मजदूरों के पलायन में उल्लेखनीय वृद्धि है। इस बार हम जिन नौ घरों में लौटे, उनमें से सात में काम करने के लिए कम से कम एक परिवार का सदस्य अस्थायी रूप से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश चला गया था। ये 15 से 40 वर्ष की आयु के बीच के पुरुष परिवार के सदस्य थे; इन आयु समूहों में दो परिवारों में बिना प्रवासियों के कोई पुरुष नहीं थे। ऐसा माना जाता था कि दुबैली विश्वासपुर के 76% सबसे गरीब घरों में, मुस्लिम और हिंदू दोनों, प्रवासी थे। पोखरिया में 150 घरों के अनुमानित 250 प्रवासी रहते थे। यह स्पष्ट था कि प्रवास बड़े पैमाने पर हो रहा था, भले ही ये अनुमान केवल अनुमान हैं। यह निस्संदेह मजदूरी वृद्धि का मुख्य कारण है और इसने गाँवों में श्रम आपूर्ति और मांग संतुलन को काफी बदल दिया है। यह प्रवास मौसमी, क्षणिक और पुरुष था। मानसून के मौसम को छोड़कर, प्रवास वर्ष के किसी भी समय हो सकता है, लेकिन यह सर्दियों के महीनों में अप्रैल तक चरम पर होता है। जब हम पहुंचे तो कई प्रवासी धार्मिक अवकाश के लिए अपने गाँव लौट आए थे, इसलिए हम उनके श्रम के बारे में प्रत्यक्ष कहानियाँ सुनने में सक्षम थे। यह वास्तव में विविध था। उनमें से एक हाल ही में हरियाणा महानगर में चार महीने के निर्माण श्रम से लौटा था। एक अन्य ने अक्टूबर से मार्च तक छह महीने हरियाणा के एक गांव में कृषि में काम किया था। मुहम्मद इज़राइल, जो पहले पंजाब में कटाई कर रहे थे, ने उत्तर प्रदेश में पत्थर की पेराई की थी। रुस्तम के दो बच्चे, जिनकी उम्र 18 और 20 वर्ष है, पंजाब में कटाई कर रहे थे, जबकि उनका बेटा उत्तर प्रदेश के एक होटल में काम करता था। वे दो साल से यही कर रहे थे। 2000 में, फतकन मोची के बेटे ने गेहूं की फसल के लिए पंजाब की यात्रा की, लेकिन उन्हें 1999 में पूर्णिया शहर में नौकरी मिल गई, जो 20 किमी दूर है। दिल्ली में, एक 'मिस्त्री' ने चामरू महलदार के बेटे को प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किया। हर छह महीने में, किरू लाल बिस्वास दिल्ली में भवन निर्माण उद्योग में राजमिस्त्री के रूप में काम करते हैं। पिछले 15 वर्षों से वह हर साल घूम रहे हैं। यह चारों ओर मजदूरी का काम है। 70 रुपये के कुछ हालिया दावों के साथ, दैनिक कमाई मुख्य रूप से 60 रुपये से 75 रुपये के बीच मानी जा रही थी। एक ईंट बनाने वाले के रूप में अपने अधिक कुशल पेशे के लिए 85 रुपये प्राप्त करने वाले कीरू एक अपवाद थे। इसलिए, उत्तर-पश्चिम भारत में मजदूरी बस्ती की तुलना में कम से कम दोगुनी है।

हर किसी ने बहुत आसानी से काम मिलने की सूचना दी, हर महीने अधिक से अधिक कुछ दिनों की बेरोजगारी के साथ, और प्रवास की अवधि एक बार में एक महीने से छह महीने तक भिन्न थी। दिल्ली क्षेत्र की वापसी यात्रा में लगभग 360 रुपये का खर्च आता है। अधिकांश प्रवासियों या उनके परिवारों ने प्रति प्रवासी श्रमिक 500 रुपये से 1,000 रुपये प्रति माह के बीच बचत या प्रेषण की सूचना दी, जो संभवतः कुल आय का लगभग आधा है। दो महीने की अनुपस्थिति के बाद, रुस्तम के प्रत्येक लड़के

ने 1,000 रुपये वापस कर दिए। एक महीने तक काम करने के बाद, फा मोची का बेटा पंजाब से 800 रुपये लेकर लौटा। डी में छह महीने के बाद, कीरू (जो अधिक कमाई करता है) 7,000-8,000 रुपये लाया। यह राशि क्षेत्र में एक सांस्कृतिक श्रमिक गृह की पूरी आय की तुलना में महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यह रुस्तम के लिए परिवार की आय का केवल आधा हिस्सा प्रदान करता है, जिसके दो बच्चे सालाना चार महीने पंजाब में बिताते हैं। यह आय पर समग्र प्रभाव को बढ़ा-चढ़ाकर बताता है क्योंकि यदि प्रवास नहीं होता तो उन्हें स्वाभाविक रूप से समुदाय में कुछ नौकरी मिल जाती। हालांकि, इसके लिए लेखांकन के बाद भी, परिवार की आय में शुद्ध योगदान अभी भी 30 से 40 प्रतिशत के बीच हो सकता है। इसके अलावा, पलायन से प्रत्यक्ष आय का प्रवाह ग्रामीण श्रम बाजार में वेतन में भारी वृद्धि के कारण कृषि श्रमिक परिवारों की आय में वृद्धि के अलावा है। जैसा कि हम देख सकते हैं, 1970 के दशक में गांवों में वेतन सपाट या घट रहा था, लेकिन 1981 और 1999 के बीच (फसल को छोड़कर) वे चार गुना हो गए। यह कहना शायद अतिशयोक्ति नहीं है कि घर में युवा वयस्क पुरुष सदस्यों की संख्या के आधार पर, प्रवासन के प्रत्यक्ष प्रभावों और मजदूरी पर इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव दोनों को ध्यान में रखते हुए कृषि श्रमिक परिवारों के लिए वास्तविक आय में दो से तीन की वृद्धि हुई है। इस आवधिक पलायन के बारे में कुछ भी असामान्य नहीं था। मौसमी प्रवास का उल्लेख पहले 1981 में किया गया था। हालाँकि, उस समय प्रवास काफी कम था। यह अनिवार्य रूप से एक उत्तरजीविता रणनीति थी जो आय बढ़ाने और धन को संरक्षित करने के बजाय मौसमी बेरोजगारी की भरपाई करती थी। इन दिनों, गाँव की श्रम आवश्यकता की डिग्री की परवाह किए बिना प्रवास होता है। रोजगार संबंध में बदलाव अभी तक, इन श्रम बाजार बदलावों से गांवों के व्यावसायिक पैटर्न में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है। कुछ रोजगार विविधीकरण के बावजूद, विशेष रूप से वाणिज्य और परिवहन के क्षेत्रों में, कृषि रोजगार का प्राथमिक स्रोत बना हुआ है। 1981 में, अधिकांश माध्यमिक व्यवसाय अभी भी गैर-कृषि कार्य और समुदाय में स्व-रोजगार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। हालाँकि, गाँव के श्रम बाजार में नौकरी के आदान-प्रदान की प्रकृति में काफी बदलाव आया है। स्थायी श्रम में कमी सबसे उल्लेखनीय प्रवृत्ति है। 1981 में बड़ी संख्या में स्थायी हलवाले (हलवाहा) गायब हो गए हैं, और लगभग सभी कृषि मजदूर अब आकस्मिक, दैनिक वेतन पाने वाले मजदूर हैं। उत्पादकों का कहना है कि वे अब उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं; इज़राइल, जो आठ या नौ साल पहले तक हलवाहा था, ने दावा किया कि उसने छोड़ दिया क्योंकि पैसा पर्याप्त नहीं था (i.e., वह कहीं और अधिक कमा सकता था) यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि ट्रैक्टर अब सस्ती दरों पर किराए पर लिए जा सकते हैं। इस प्रकार, आपूर्ति और मांग दोनों पक्ष वैकल्पिक संभावनाओं की उपस्थिति से प्रभावित होते हैं। कथित तौर पर अभी भी कुछ युवा लड़के स्थायी दास (चारवाहा) के रूप में काम कर रहे थे, हालांकि वे कथित तौर पर 1982 में कुल का एक छोटा प्रतिशत थे। इस परिवर्तन का वर्णन करना अधिक कठिन है। एक स्पष्टीकरण यह हो सकता है कि हालांकि विचाराधीन पुरुषों के स्कूल जाने की अधिक संभावना है, कृषि श्रमिक घरों के बच्चों की उपस्थिति दर वास्तव में लगातार कम है। एक अन्य व्याख्या स्थानीय श्रम बाजार की कठोरता हो सकती है, जिससे बच्चों के लिए अंशकालिक नौकरियां ढूंढना आसान हो जाता है जो अच्छी तनख्वाह देती हैं।

यह संभवतः मध्यम आकार के किसानों के बीच संसाधनों की कमी का भी संकेत देता है, जिनकी वास्तविक आय स्थिर हो गई है जबकि कृषि मजदूरों की आय में वृद्धि हुई है। एक बार फिर, आपूर्ति और मांग दोनों ताकतें होने की संभावना है। महिला श्रम बल की भागीदारी कार्य बाजार का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कुछ संकेत थे कि 1981 में महिला श्रम बल की भागीदारी बढ़ रही थी। यह पता लगाने के अलावा कि महिला श्रम बल की भागीदारी सबसे कम थी जब वेतन सबसे अधिक था, हम उस समय मानते थे कि यह किसी भी सामाजिक बदलाव की तुलना में तीव्र आवश्यकता का प्रतिबिंब था। 1999 में कृषि श्रमिक परिवारों में महिलाओं के लिए कटाई प्राथमिक कार्य था, और फिर भी, वे मुख्य रूप से अपने पतियों के साथ पारिवारिक समूहों में काम करती थीं। बहुत कम आय वाले परिवारों में भी मुस्लिम महिलाओं ने शायद ही कभी निराई या प्रत्यारोपण में भाग लिया हो। रुस्तम की साली अपनी आय की कमी को लेकर कुछ परेशान थी, लेकिन फिर भी वह केवल कटाई और कटाई के बाद के काम करती थी। महिलाओं के हरिजन घरों में अन्य कृषि कार्यों (निराई और प्रत्यारोपण) में काम करने की अधिक संभावना है, उन घरों की तुलना में जिनके पास भूमि या अन्य पर्याप्त

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 11, Issue: 4 | October – December 2024

राजस्व स्रोत हैं। महिलाओं के कई अन्य व्यवसायों में काम करने की अधिक संभावना है, जैसे कि दुकानदारी, खाद्य प्रसंस्करण और टोकरी बनाना। इसके अतिरिक्त, कुछ व्यवसाय सेक्स-टाइप किए गए हैं, जिसमें दाई सबसे प्रमुख उदाहरण है। हालाँकि, महिलाएं अभी भी ज्यादातर घर तक ही सीमित हैं, जहाँ वे जानवरों की देखभाल करती हैं, ईंधन इकट्ठा करती हैं, भोजन तैयार करती हैं और बच्चों की देखभाल करती हैं। यह स्पष्ट है कि पुरुषों के पलायन के परिणामस्वरूप स्थानीय श्रम बाजार में महिलाओं के पास रोजगार के अधिक विकल्प हैं। दूसरी ओर, उच्च आय को महिला श्रम बल की भागीदारी की आवश्यकता को कम करने के रूप में देखा जा सकता है। ये दोनों प्रतिस्पर्धी कारक या तो कमजोर हैं या एक दूसरे को रद्द कर देते हैं, जैसा कि महिलाओं की श्रम बाजार भागीदारी में बदलाव की कमी से देखा जाता है। भोजन और उपभोग जैसे-जैसे दुकानों की संख्या बढ़ी है, यह स्पष्ट है कि राजस्व में इस वृद्धि के कारण खपत में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, दुबैली विश्वासपुर गाँव में वर्तमान में चार आटा मिलें हैं, जिनमें से तीन 1981 से काम कर रही हैं। सबसे निम्न आर्थिक वर्ग अब पहले की तुलना में अधिक प्रकार के खाद्य पदार्थ खाते हैं। पिछले हफ्ते, रुस्तम, जो एक मजदूर और बटाईदार घर से आती है, ने हर दिन खाने के लिए पर्याप्त सब्जियां खरीदीं: एक किलोग्राम साजन (एक हरी सब्जी) दो बंडल सैग (पालक) एक किलोग्राम प्याज, और दो किलोग्राम आलू। औसतन, 1981 में कृषि श्रमिकों के परिवारों को हर दो दिन में सिर्फ एक बार सब्जियां मिलती थीं। इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि गरीब आबादी अब कम अनाज का सेवन नहीं करती है, जैसे कि बाजरा, जिसे कभी आहार का हिस्सा माना जाता था। बिरमन लाल की पत्नी के अनुसार, वे वर्तमान में बाजरे के रूप में जाने जाने वाले निम्नतर अनाज के बजाय मक्का, गेहूं, चावल और आलू का सेवन करते हैं। लेकिन सभी उत्तरदाताओं ने नहीं सोचा कि चीजें बेहतर हो गई हैं; कई लोगों ने कहा कि उन्होंने जो भोजन खाया वह बेहतर होने के बजाय बदतर हो गया था। यह थोड़ा अप्रत्याशित है और दीर्घकालिक पैटर्न के बजाय कई फसल विफलताओं का परिणाम हो सकता है। इसके अतिरिक्त, कई महिला उत्तरदाताओं ने कहा कि वे अक्सर वर्ष के अन्य मौसमों के दौरान दिन में दो बार भोजन तैयार करती हैं, लेकिन असिन में प्रति दिन केवल एक बार भोजन तैयार किया जाता है। स्पष्ट रूप से अभी भी विकास के लिए बहुत गुंजाइश है। निस्संदेह कृषि श्रमिक परिवारों की आय में वृद्धि और किसानों की आय में स्पष्ट ठहराव के कारण उपभोग के स्वरूप में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। यह बदलाव अधिक शोध की आवश्यकता है क्योंकि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भविष्य के परिवर्तनों का संकेत हो सकता है। III परिवर्तन प्रक्रिया बाढ़ और उसके बाद के परिणाम स्थानीय श्रम बाजार क्यों बदल रहा है? ग्रामीण 1987 में आई विनाशकारी बाढ़ को परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में जोड़ते हैं। बहुत से लोग मारे गए और बहुत नुकसान हुआ। पशुओं और कृषि उत्पादन को बहुत नुकसान हुआ। चामरू महलदार के अनुसार, अगर वे स्थानांतरित नहीं होते तो वे जीवित नहीं रहते। उन्होंने कहा कि जब खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ीं तो श्रमिकों ने चालू वेतन के लिए काम करने से इनकार कर दिया, और जब मकान मालिकों ने मजदूरी बढ़ाने से इनकार कर दिया तो वे कहीं और रोजगार खोजने चले गए। इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पहले से ही हो रही आवाजाही की मात्रा के कारण रोजगार का पता लगाने के लिए कुछ मौजूदा संबंधों और कनेक्शनों का दोहन किया जा सकता है। हालांकि, माइग्रेशन ने अपने पिछले कार्य के विपरीत, इस उदाहरण में एक अस्थायी सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य नहीं किया।

इसके बजाय, इसने गाँव के श्रमिक संबंधों को बदल दिया। समुदाय के बाहर, प्रवासी रोजगार खोजने और अधिक पैसा कमाने में सक्षम थे। इसके अलावा, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्रमिक विस्तार, जो पश्चिमी भारत में केंद्रित था, ने बाद के वर्षों में प्रवासियों के अवशोषण के लिए अधिक से अधिक संभावनाएं पैदा कीं। इस प्रक्रिया में किसी न किसी तरह से बेहतर संचार शामिल होना चाहिए था। समुदाय की हर मौसम में चलने वाली सड़क के कारण बाहरी दुनिया से जुड़ाव आसान हो गया और गाँव में टेलीफोन सेवाएं भी पहुंच गई हैं। उपभोग की आदतों में परिवर्तन और बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों में वृद्धि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह के परिणामस्वरूप हुई है। इसलिए, जब परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो अन्य चरों ने इसे मजबूत किया। बाढ़ आपदा के बिना भी, सबसे अधिक संभावना है कि बदलाव अंततः हुआ होगा, लेकिन एक झटके ने प्रक्रिया शुरू करने में मदद की। आय के वितरण पर प्रभाव इस दृष्टिकोण का गाँव की बिजली और आय वितरण पर महत्वपूर्ण

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 11, Issue: 4 | October – December 2024

प्रभाव पड़ा है। आम तौर पर, पलायन कृषि मजदूरों और छोटे किसानों तक ही सीमित है। कम से कम दुबैली विश्वासपुर में दो से तीन हेक्टेयर क्षेत्र में बहुत सारी जोतें हैं, और चार हेक्टेयर या उससे अधिक के साथ एक बड़ी संख्या है, इस तथ्य के बावजूद कि वे विशेष रूप से बड़े मालिकों वाले गाँव नहीं हैं। स्थानीय संदर्भ में, ये बड़ी जोत हैं, और इस तरह की जोत वाले किसान पश्चिमी भारत में पाए जाने वाले कम कुशल मजदूरी वाले श्रमिकों की तलाश में कृषि मजदूरों के साथ यात्रा नहीं करते हैं, जहां वे अंततः बहुत कम पैसा कमाएंगे। समग्र प्रभाव यह है कि गाँव के निम्न आय समूह नई नौकरी और आय की संभावनाओं का केंद्र रहे हैं। हालांकि, जैसा कि हमने दिखाया है, हालांकि मजदूरों की वास्तविक मजदूरी में काफी वृद्धि हुई है, मध्यम और बड़े पैमाने पर किसानों की वास्तविक कृषि आय संभवतः स्थिर हो गई है या कम भी हो गई है। बेहतर आय वाले लोग अपने गाँव के बाहर उच्च-वेतन वाले रोजगार बाजारों तक पहुँचने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा ज्यादातर अपने बच्चों की शिक्षा में किए गए निवेश के कारण प्रतीत होता है, जिसके बाद वे स्थायी रूप से स्थानांतरित हो जाते हैं। उच्च आय श्रेणियों की तुलना में, कृषि मजदूरों को प्रवास में वृद्धि से आनुपातिक रूप से अधिक लाभ हुआ है। नतीजतन, आय असमानता में कमी आई है, शायद काफी हद तक।1. श्रम बाजार की कार्यप्रणाली में बदलाव दक्षता वेतन मॉडल के एक पोषण आधारित संस्करण ने 1971 और 1981 [जी रॉजर्स 1975] में मजदूरी-निर्धारण प्रक्रिया का सबसे अच्छा समग्र विवरण प्रस्तुत किया। श्रम की अधिकता थी, और ऐसा प्रतीत होता था कि नियोक्ता बाजार के बजाय अपने कर्मचारियों की श्रम क्षमता के आधार पर वेतन निर्धारित करते थे। हालाँकि, मजदूरी प्रणाली के कई पहलुओं ने उस दिशा की ओर इशारा किया। उदाहरण के लिए, मजदूरी का एक बड़ा हिस्सा सीधे श्रमिक को भोजन के रूप में दिया जाता था, और मजदूरी धीरे-धीरे समायोजित होने लगती थी ताकि समग्र आय औसतन लगभग स्थिर रहे, लेकिन अल्पकालिक मांग में उतार-चढ़ाव के लिए बहुत अधिक प्रतिक्रिया नहीं दी। यह एक सरलीकरण है, और मजदूरी और उसके भुगतान को निर्धारित करने में कई विशिष्ट संस्थागत पहलू शामिल थे। इस प्रणाली का एक अनिवार्य घटक कार्यबल पर नियंत्रण था, जिसे विभिन्न प्रकार के संलग्नकों, ऋण और फसल के हिस्से के माध्यम से प्राप्त किया गया था, जो आय के पूरक थे, लेकिन राशन किया गया था ताकि केवल भरोसेमंद श्रमिकों और उनके परिवारों को कटाई कर्तव्यों के लिए सौंपा जा सके। 1999 तक रोजगार बाजार के मार्गदर्शक सिद्धांतों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। बाजार के दबावों के कारण, मजदूरी में काफी बदलाव आ रहा था और यह 1981 की तुलना में कहीं अधिक थी। जब वेतन 1.5 किलोग्राम अनाज के बराबर के करीब है, जैसा कि 1981 में था, तो पोषण और ऊर्जा संबंधी चिंताओं को निस्संदेह प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि, तीन किलो अनाज के बराबर मजदूरी पर, वे काफी कम महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

प्रवास के परिणामस्वरूप श्रमिकों ने बाजार शक्ति भी प्राप्त की क्योंकि इसने उन्हें अधिक विकल्प प्रदान किए। महिलाओं के पास स्पष्ट रूप से बहुत कम बाजार शक्ति है, जो पुरुषों और महिलाओं के बीच महत्वपूर्ण वेतन अंतर में योगदान देता है। लगभग हर नौकरी संबंध आकस्मिक हो गए हैं। हालांकि, वर्तमान में कई शहरी श्रम बाजारों में देखी जाने वाली आकस्मिकता और अनौपचारिकता प्रक्रियाओं के विपरीत, आकस्मिक काम में वृद्धि नई राजस्व संभावनाओं का परिणाम है जो स्थायी श्रम द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा और लाभों की भरपाई से अधिक है। हमारे पास केवल उपाख्यानात्मक साक्ष्य हैं, लेकिन बहुत सारे पारंपरिक ब्याज श्रम लगाव से जुड़े थे। इस प्रक्रिया के बाद संभवतः भूमि मालिकों या साहूकारों से पारंपरिक ब्याज में कमी आई है। मूल रूप से। स्थानीय जमींदारों का अपने कर्मचारियों और ग्रामीण श्रम बाजार पर अधिकार कमजोर हो गया है। निस्संदेह, बड़े भूस्वामियों के राजनीतिक प्रभाव को कम करने वाले दबावों को धन के बेहतर वितरण ने और बढ़ा दिया है। समग्र परिणाम अर्ध-सामंती प्रक्रियाओं में कमी आई है। इस कार्य के पिछले मसौदे पर एक टिप्पणी में, प्रधान प्रसाद ने प्रस्ताव दिया कि बड़े भूस्वामियों की सापेक्ष स्थिति में कमी प्रवास और श्रम बाजार संबंधों के साथ-साथ ग्रामीण गरीबों के बीच बढ़ते उग्रवाद सहित कई कारकों के संयोजन के कारण हुई है, जो खुद को बढ़ती हिंसा में प्रकट करता है। हालाँकि यह दक्षिणी बिहार में अधिक आम है, लेकिन यह उत्तरी बिहार में भी महत्वपूर्ण हो सकता है। हालाँकि, विचाराधीन दोनों गाँवों में संगठित उग्रवाद या रक्तपात का कोई आरोप नहीं था। भले ही श्रम बाजार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, लेकिन सभी सामाजिक और आर्थिक संस्थानों में समान स्तर का परिवर्तन नहीं देखा गया है। हम पहले भी देख चुके हैं कि रोजगार बाजार में महिलाओं की स्थिति

नहीं बदली है। अभी भी कुछ अतिरिक्त स्थापित संस्थान हैं। हार्वेस्ट शेयर भुगतान फसल के हिस्से का भुगतान फसल के वेतन के रूप में करना एक लंबे समय से चली आ रही प्रथा है। अर्ध-सामंती प्रणाली के तहत फसल के शेयर महत्वपूर्ण थे क्योंकि वे निर्भरता को बढ़ावा देते हुए मजदूरी श्रमिकों को उत्पादन में अधिकार देते थे। इसके अतिरिक्त, यह मजदूरी श्रमिकों के वार्षिक राजस्व की एक बड़ी राशि थी। मुद्रा वेतन के साथ जो हुआ है, उसके बिल्कुल विपरीत, हालांकि, फसल मजदूरी का वास्तविक मूल्य नहीं बढ़ा है क्योंकि पिछले 20 वर्षों में श्रमिकों को मिलने वाले हिस्से में कमी आई है, जिससे उत्पादन में सुधार हुआ है। फसल मजदूरी का वास्तविक मूल्य वर्तमान में प्रवासियों की तुलना में काफी कम है और अन्य उद्योगों में वेतन के बराबर है। नतीजतन, फसल का हिस्सा अब अतिरिक्त राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है। हार्वेस्टरिचुअल और जजमानी, निश्चित रूप से, पुराने आर्थिक ढांचे के दो अप्रत्याशित अवशेष हैं जो कुछ प्रकार के जजमानी भुगतानों से संबंधित हैं। पोखरिया में अभी भी गाँव के नाई को भुगतान करने के लिए प्रति वयस्क विवाहित व्यक्ति चावल की एक काठा (आठ पौंड) की नियमित वार्षिक दर का उपयोग किया जाता था; जिनके पास भूमि नहीं थी, उन्हें इसके स्थान पर तीन दिनों का काम करना पड़ता था। यहां तक कि जो प्रवासी महीनों तक घर से दूर रहते हैं, वे भी उतना ही भुगतान करते हैं।

उपसंहारः

इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 1 अगस्त, 1987 में "टुवर्ड्स ए थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेमी-फ्यूडल एग्रीकल्चर" और उसी लेखक के अन्य लेखन।ग्रीष्मकालीन धान को उस भूमि पर उगाया जा सकता था (सिंचित) जिस पर गेहूं बर्बाद हो गया था और इसलिए आंशिक रूप से उसी उगने के मौसम का उपयोग किया जाता है।ये मोटे अनुमान औसत जलवायु स्थितियों के साथ एक वर्ष के अनुरूप होंगे। सीमित डेटा आधार को देखते हुए, वे स्पष्ट रूप से अनिश्चितता के काफी अंतर के अधीन हैं।इन गणनाओं में कई अन्य कारकों को ध्यान में नहीं रखा गया है-उदाहरण के लिए, कृषि और कृषि श्रमिकों के परिवारों के बीच जनसंख्या वृद्धि में अंतर। हालांकि, हम मानते हैं कि इन अनुमानों द्वारा निहित गुणात्मक तस्वीर व्यापक रूप से सटीक है।जबकि अनाज की समानता वास्तविक आय के लिए केवल एक अनुमानित मार्गदर्शक है, गाँव में कृषि मजदूरों के बजट में अनाज अब तक खर्च की सबसे बड़ी वस्तु है।गेहूं के लिए अपेक्षाकृत कम कीमत इस तथ्य को दर्शाती है कि साक्षात्कार गेहूं की फसल के ठीक बाद हुए।यह अनुमान इंडियन लेबर जर्नल में प्रकाशित बिहार के लिए स्प्लिसिंग टुगेदर श्रृंखला द्वारा प्राप्त किया गया है। अखिल भारतीय आंकड़ा थोड़ा अधिक है (412) कृषि श्रम के लिए मूल्य सूचकांक की गणना अब 1986-90 = 100 के आधार पर की जाती है, और वजन को उसी समय संशोधित किया गया था। पहले के आंकड़े 1970-75 = 100 के आधार पर थे। यह कई कारकों पर निर्भर करेगा, जिसमें डंठल की तुलना में कान का वजन, यह हाथ से कटाई की गति को कैसे प्रभावित करता है, कटाई में लगने वाला समय आदि शामिल हैं। जैसे-जैसे उपज बढ़ती है, कटाई और कटाई के लिए प्रति हेक्टेयर आवश्यक श्रम निवेश भी बढ़ता है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि समान अनुपात में नहीं। हालाँकि, चूंकि 1999 में गेहूं की फसल ने असाधारण रूप से कम पैदावार की, इसलिए उस वर्ष में प्रतिफल वास्तव में बहुत कम था। आजीविका और गरीबी के संबंध में प्रवास की भूमिका की डी हान की समीक्षा में अधिकांश अध्ययनों का हवाला दिया गया है जो सुझाव देते हैं कि प्रवास असमानता को बढ़ाता है, हालांकि उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि इसे सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है। इस मामले में, यह संभावना प्रतीत होती है कि यहाँ प्रवास का रूप गाँव के भीतर असमानता को कम करता है, और उत्तर-पूर्वी बिहार और उत्तर-पश्चिमी भारत के बीच असमानता को भी कम करता है, लेकिन उत्तर-पश्चिमी भारत के भीतर असमानता को बढ़ा सकता है, क्योंकि बिहारी और अन्य प्रवासी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अकुशल मजदूरी को कम करते हैं।यह प्रवास का एक पहलू है जिस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

References:

1. See Jan Breman and Arvind Das, Down and Out: Working under Global Capitalism, Delhi, OUP, 2000, for some examples of the working conditions of migrants in Gujarat which support this point. References 14.
2. Breman, Jan and Arvind Das (2000): Down and Out: Working under Global Capitalism, OUP, New Delhi. De Haan, Arjan (1999):
3. 'Livelihoods and Poverty: The Role of Migration - a Critical Review of the Migration Literature' in The Journal of Development Studies, Vol 36, No 2, December. Prasad, H S Pradhan (1987): 'Towards a Theory of Transformation of Semi-feudal Agri- culture' in Economic and Political Weekly, August 1. Rodgers, G (1973):
4. 'Effects of Public Works on Rural Poverty: Some Case Studies from the Kosi Area of Bihar', Economic and Political Weekly, Vol viii, Nos 4-6, Annual Number, February. - (1975):
5. 'Nutritionally-based Wage Deter- mination in the Low-Income Labour Market', Oxford Economic Papers. Rodgers, G and R Rodgers (1984):
6. 'Incomes and Work among the Poor of Rural Bihar, 1971- 1981, Economic and Political Weekly, Vol XIX, No 13, Review of Agriculture, March. Sharma, Naresh and Jean Dreze (1998):
7. 'Tenancy, in Peter Lanjouw and Nicholas Stern (ed), Economic Development in Palanpur over Five Decades, New Delhi,